International Journal of Education and Science Research Review
Volume-11, Issue-4 July-August-2024 E-ISSN 2348-6457
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Impact Factor - 7.02 Email- editor@ijesrr.org

बैंकों में आज महिलाओं के वित्तीय समस्याओं का एक अध्ययन

डा गोपाल स्वरूप शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय अरनिया बुंलदशहर (उत्तर प्रदेश)

सारांश, पीएमजेडीवाय जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के बावजूद निम्न आयवर्ग वाले घरों की महिलाएं बचत के लिए बैंकों के इस्तेमाल से क्यों झिझकती हैं और उनके नजरिए को कैसे बदला जा सकता है? उत्तर प्रदेश के नयागांव मथुरा जनपद की फूलबानो जरी का काम करती हैं। अपने तीन बच्चों के साथ वे गांव में ही रहती हैं। जब से फूलबानो के पति काम की तलाश में दिल्ली गए हैं, तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही आ गई है। वे कहती हैं कि ”राजेश नाम के एक बिजनेस करेसपॉन्डेंट ने मुझे बताया कि मेरे कपड़ों या खाने के डब्बों में छिपाए गए पैसे या तो चोरी हो सकते हैं या फिर खर्च हो सकते हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि इतने कम पैसों को भी बैंक में जमा करवाया जा सकता है। ऐसा करना अधिक सुरक्षित है और लम्बे समय तक बचत करने से भविष्य में मुझे बैंक से कर्जा लेने में आसानी होगी।” फूलबानो की पड़ोसन शरीना बी एक छात्र होने के साथ–साथ अपना घर भी सम्भालती हैं। वे भी औपचारिक बचत के महत्व को समझती हैं। शरीना का कहना है कि ”केवल बचत से ही कोई आगे बढ़ सकता है और तरकी कर सकता है। अगर मैं बचत करूंगी तो उससे मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूं।” बचत महिलाओं को जरूरी आर्थिक सुरक्षा और आजादी दे सकती है और मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर सकती है। हालांकि, भारत में फूलबानो और शरीना जैसी महिलाओं की कहानी आम नहीं है। 2024–25 में 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखने वाले इस देश को चाहिए कि यह वित्तीय समावेश (फायनेंशियल इन्क्लूजन) के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश करे। यदि महिलाएं उपयोगी और किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठा पाएंगी तो उनके सामने पैसे कमाने, सम्पत्ति बनाने और उनके जीवन से जुड़े फैसले लेने के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्य शब्द, महिलाएं, अर्थव्यवस्था, बचत, बीमा, माइक्रो–इंश्योरेंस, पेंशन आदि

प्रस्तावना, प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाय) जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य पिछड़े समुदायों से आने वाले हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। यह उद्देश्य इस संदर्भ में भारत की विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, पीएमजेडीवाय ने लाखों देशवासियों को बैंक में पैसे जमा करने का अवसर दिया है। 2014 में अपने लॉन्च के बाद से इस योजना के तहत खुलने वाले बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ और अगस्त 2022 में 46.25 करोड़ हो गई थी। यह भी गौर करने वाली बात है कि महिलाएं अपने पीएमजेडीवाय खातों का उपयोग बचत के अलावा, सरकारी पहलों से मिलने वाले लाभों के लिए भी सक्रियता से करती हैं। विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग में हमारे शोध से इस बात की पुष्टि हुई है कि ग्रामीण तथा निम्न आय वर्ग की महिलाएं ऐसा मानती हैं कि बैंक उनके और उनकी छोटी बचतों के लिए नहीं होते हैं। इसके अलावा, इंक्लूसिव फायनांस इंडिया रिपोर्ट

2022 के अनुसार 12.7 करोड़ वयस्कों ने पहली बार सीधे डिजिटल भुगतान सुविधा का इस्तेमाल कोविड–19 महामारी के दौरान किया था। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं डिजिटल लेनदेन को लेकर कम सहज होती हैं।

आज वह क्या है जो महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग से दूर रखता है?

बेशक, महिलाएं सहज रूप से बचत करने वाली होती हैं लेकिन सभी महिलाएं बैंकों में औपचारिक रूप से बचत नहीं करती हैं। इसके लिए वे अपने घरों में पैसा रखने जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही भरोसा करती हैं। बचत करने, खातों को चलाने और क्रेडिट हिस्ट्री या अन्य वित्तीय उत्पादों जैसे माइक्रो–इंश्योरेंस, पेंशन या लघु ऋण आदि के जरिए वित्तीय मामलों से गहराई से जुड़ना महिला ग्राहकों की प्राथमिकता नहीं होती है। इसके कई कारण हैं, सबसे बड़ा तो यह है कि महिलाएं अपनी आमदनी को नगण्य मानती हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है कि उनके थोड़े से पैसे बैंकों में जमा करने लायक नहीं हैं। पारम्परिक रूप से भी महिलाओं को आर्थिक फैसले लेने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है और इसलिए स्वायत्ता को लेकर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इससे अक्सर ही उन्हें बचत के अपने ऐसे तरीके विकसित करने पड़ते हैं जो उन्हें सबकुछ नियंत्रण में होने का एहसास करवा सकें। नतीजतन, महिलाएं बैंक को अपने लिए बचत करने की जगह के रूप में नहीं देखती हैं दृ विशेष रूप से 'छोटी सी' राशि के लिए क्योंकि यह उन्हें अपरिचित और अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है। उदाहरण के लिए, हमारे शोध से यह भी पता चला है कि ग्रामीण महिलाओं के अपने नाम से बैंक में खाते हैं लेकिन वे उनका उपयोग नहीं करती हैं। ग्रामीण महिलाओं के पास आमदनी के ऐसे कुछ ही स्त्रोत होते हैं जिन्हें वे अपना कह सकती हैं। अपने परिवार की खेती से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने और काम करने के बावजूद वे खुद को परिवार की आमदनी में योगदान देने वाले के रूप में नहीं देखती हैं।

वित्तीय समावेशन से परे, बैंकों के लिए महिला ग्राहकों में निवेश करने की एक व्यावसायिक वजह भी है। चित्र साभारः वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग

आज महिलाऐं अपने घर के आर्थिक तथा वित्तीय फैसलों में भी सक्रियता से भाग नहीं लेती हैं और ना ही अपने पीएमजेडीवाय खातों में आने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर्स (डीबीटी) यानी सीधे आने वाले पैसों का लाभ ही उठा पाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं का कोई खास उपयोग या महत्व नहीं दिखाई देता है। भारत के शहरों की स्थिति थोड़ी अलग है। शहर की महिलाएं काम से होने वाली आमदनी से अपना जीवनयापन करती हैं। साथ ही, वे अपने पीएमजेडीवाय खातों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों के लिए उपयोग में लाती हैं। लेकिन आमतौर पर शहर की महिलाएं भी इन खातों में बचत के पैसे जमा नहीं करतीं हैं। हमारे शोध में यह बात सामने आई कि शहरी इलाकों में निम्न आयवर्ग की महिलाओं को बैंक में पैसे जमा करना सुविधाजनक नहीं लगता है और वे स्थानीय बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के बारे में नहीं जानती हैं। यह उनके व्यवहार और नजरिए में बदलाव न आने का एक बड़ा कारण है। वित्तीय समावेशन के अलावा बैंकों के लिए अपनी महिला ग्राहकों में निवेश करने का एक व्यावसायिक कारण भी है। हमारा अनुमान है कि यदि निम्न आयवर्ग की लगभग 10 करोड़ महिलाएं बैंक में बचत के पैसे जमा करवाना शुरू करती हैं तो उस स्थिति में बैंक 2 करोड़ लाभार्थियों को 10,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट और जमा में 20,000 करोड़ रुपए के इनफ्लो की स्थिति में आ सकते हैं।

मैंने अपने देश के महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में महिलाओं को उनके पीएमजेडीवाय खाते के विभिन्न इस्तेमालों के लिए जन धन प्लस प्रोग्राम चलाया। हमने पाया कि जब पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही सक्रिय रूप से पीएमजेडीवाय (हर साल कम से कम चार बार खाते में लगभग 500 रुपए जमा करना) खातों का उपयोग करते हैं, तब महिलाओं का औसत बैंक बैलेंस पुरुषों की तुलना में 30 फीसद अधिक होता है और महिला ग्राहक का आजीवन रेवेन्यू भी पुरुष ग्राहक के आजीवन रेवन्यू से 12 फीसद ज्यादा होता है। ऐसा महिलाओं के खातों में अधिक पैसे होने के कारण होता है। इससे यह और भी जरूरी हो जाता है कि बैंक अपने महिला ग्राहकों को अधिक गम्भीरता से लेना शुरू करें। हमें भारत के शहरी, ग्रामीण एवं उपनगरीय इलाकों के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के साथ काम करने का अनुभव है। अपने इन अनुभवों के दौरान हमने पाया कि सबसे पहले घरों और सार्वजनिक जगहों पर जाकर महिलाओं से बातचीत करना जरूरी है। ताकि उनके लिए उनसे संबंधित एवं सांस्कृतिक रूप से अनुकूल मार्केटिंग अभियानों के तहत उनमें जागरूकता फैलाई जा सके। यह सबसे मुख्य काम है क्योंकि निम्न आय वाली ज्यादातर महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है लेकिन वे अन्य महिलाओं के साथ समूह बनाकर बाहर जा सकती हैं। बैंकिंग करेसपॉन्डेंट (बीसी) और बीसी सखी (सामुदायिक स्तर पर महिला बैंकिंग एजेंटों के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नियुक्त) महिला पीएमजेडीवाय ग्राहकों तक पहुंचने में सबसे अधिक प्रभावी नेटवर्क साबित होते हैं। शहरी इलाकों में बीसी के सम्पर्क में रहने वाली 32 फीसद महिलाएं बैंक में बचत के बारे में सोचती हैं, वहीं 18 फीसद महिलाओं ने बचत की अपनी इस आदत को बरकरार रखा है।

हालांकि, बैंक अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बीसी के नेटवर्क विकास में निवेश तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सभी बैंक करेसपॉन्डेंट्स के पास यह कौशल नहीं होता कि वे सरकार से मिलने वाले लाभों के हस्तांतरण के अलावा ग्रामीण इलाकों में महिला पीएमजेडीवाय खाता धारकों को जोड़ सकें। अधिकांश बीसी केवल कैश–इन और कैश–आउट मुहैया करवाने पर ही ध्यान देते रहे। जन सुरक्षा बीमा और पेंशन योजनाओं जैसे अन्य उत्पादों में महिलाओं को निवेश के लिए सक्रियता से प्रोत्साहित करने वाले बीसी भी संख्या में बहुत कम मिले। बैंकों को बीसी तथा बीसी सखियों की क्षमता को बढ़ाने में निवेश करने की आवश्यकता है। अच्छे से संवाद करने वाले और संबंधों को महत्व देने वाले बीसी, महिला ग्राहकों के साथ बेहतर सम्पर्क स्थापित करने में सक्षम थे और उन्हें अपने खातों में बचत का पैसा और बीमा या पेंशन जैसी योजनाओं में पैसे के निवेश को बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। चाहे यह ग्रामीण इलाकों में बीसी केंद्र से संचालित होने वाला बीसी हो या फिर शहरी इलाकों में किराना दुकानों से संचालित होने वाले बीसी। महिला ग्राहकों तक लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुख्य नेटवर्क के साथ भरोसेमंद रिश्ता बनाने की जरूरत है। शहरी इलाकों में बीसी की सफलता दर तीन गुना अधिक है जहां वे निम्न–आयवर्ग की महिला ग्राहकों को अन्य वित्तीय सेवाओं में शामिल कर पाते हैं। बीसी सक्रिय रूप से महिला ग्राहकों को शामिल कर उन्हें बीमा और पेंशन की क्रॉस–सेलिंग करके बेहतर रेवेन्यू और कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्रेडिट हिस्ट्री बनाने, कर्ज और क्रेडिट प्राप्त करने और बचत को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसलिए बैंकों को बीसी तथा बीसी सखियों की क्षमता को बढ़ाने में निवेश करने की आवश्यकता है। इन एजेंटों, विशेष रूप से महिला एजेंटों को व्यापार प्रबंधन और निम्न आय वाले या ग्रामीण महिला ग्राहकों को सेवा देने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता (जेंडर सेंसिटिविटी) का प्रशिक्षण दिया जाए। बैंकों और आजीविका मिशनों को बीसी और बीसी सखियों के पर्यवेक्षण का समर्थन करने के लिए निवेश करना चाहिए। साथ ही, उन्हें नेटवर्क को मजबूत करने और अधिक लोगों को बैंकिंग एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा समय–समय पर उनकी सेवाओं को पहचानने के साथ–साथ उनके काम पर फीडबैक भी देना चाहिए। महिला–केंद्रित डिजाइन का नजरिया महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने और बैंकों में बचत जमा करने में आने वाली बाधाओं से निपटने पर केंद्रित होता है। बचत करने के लिए एक सहज स्थान के रूप में बैंक का एक मेंटल मॉडल बनाना, महिलाओं के लिए सुलभ और विश्वसनीय चौनलों का उपयोग करके बैंकों में बचत करना आसान बनाना, बचत को सहज और फायदेमंद बनाना, उन्हें औपचारिक रूप से बचत करने की आदत बनाने के लिए प्रेरित करना और याद दिलाते रहना, एक मजबूत महिला–से–महिला बैंकिंग नेटवर्क तैयार करना, और महिलाओं के लिए उपयुक्त और सरल बैंकिंग उत्पाद बनाना निश्चित रूप इस दिशा में लिए जाने वाले सही कदम हैं। डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने से भारत की अर्थव्यवस्था और लिंग–समावेशी वित्त की संभावनाओं को सामने लाया जा सकता है। अंत में, महिला ग्राहकों के व्यवहार में अंतर को समझने के लिए सेक्स–डिसएग्रीगेटेड आंकड़ों पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे वित्तीय समावेशन को बेहतर करने में वित्तीय संस्थानों तथा नीति–निर्माताओं को मदद मिलेगी।

आज महिला सशक्तिकरण में बैंकिंग क्षेत्र की अहम भूमिका

अपने प्रयासों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बैंकों ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है जिस कारण उन्हें भारतीय समाज में सामाजिक–आर्थिक समानता प्राप्त करने में मदद मिली है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में बना हुआ है। कई सरकारी योजनाओं और नीतिगत निर्णयों के बावजूद, भारत में महिलाएं अभी भी शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के मामले में समान अवसरों से वंचित हैं। हालांकि, विशेषकर शहरी केंद्रों में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी कई तरह के लाभों से वंचित हैं। कई सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होगा ताकि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिल सके। हम सभी जानते हैं कि एक सही समाज के निर्माण में महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। सामाजिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण में उनसे जुड़े आर्थिक मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक स्तंभों में से एक माना जाता है, इसलिए जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो बैंकों की भूमिका अहम हो जाती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपस्थिति देश के दूरस्थ कोनों में भी उपलब्ध हैं। ये बैंक पारंपरिक रूप से महिलाओं की वित्तीय बचतों और जरूरतों को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। बैंकों ने हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वह आजीविका या आय के स्थिर स्त्रोत के रूप में हो या बेहद कम आयु में शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने में वित्तपोषित योजनाए ही क्यों ना हों । सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। बैंकों द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता और ऋण योजनाओं में विशेष रियायती दरों पर ब्याज भी दिया जाता है। बैंकों द्वारा तनाव मुक्त ऋण नियमों की भी घोषणा की गयी है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सभी अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी महिलाएं अभी भी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं। इन बाधाओं के कारण महिलाएं बैंकों से सेवाओं नहीं ले पाती हैं। अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं के बारे में तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो यह एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। देश में कुल परिचालन बैंक खातों में महिलाओं का योगदान केवल 24 फीसद है और कुल जमा राशि में केवल 24ः ही महिलाओं का योगदान है। बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की इस तरह की भागीदारी को निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खासकर तब, जब ऋणों की आपूर्ति की जा रही हो। केवल 12 फीसदी व्यक्तिगत ऋण खाते ही महिलाओं से संबंधित हैं, जो स्पष्ट रूप से दो बैंकिग सेवाओं के उपयोग के बीच लिंगभेद की असमानता को प्रदर्शित करते हैं।

शोध विधि, मेने अपने इस शोध पत्र के लिऐं **सर्वेक्षणात्मक शोध विधि** का प्रयोग किया यह इस लिऐं कि मैने अनेक महिलाओं से उनकी बैंकिंग क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को अपनी आंखों से देखा है और अनेक महिलाओं से जानकारी एकत्रित कर ही मैने इस शोध पत्र को तैयार किया है।

निष्कर्ष, भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से (विशेष रूप से ग्रामीण भारत में) नवंबर 2013 में एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित देश के प्रथम महिला बैंक की स्थापना की। भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) की स्थापना के साथ एक नए

युग बैंकिंग सेवा क्षेत्र की शुरूआत हुई। बीएमबी मुख्य रूप से महिलाओं और महिलाओं के स्व–सहायता समूह (एसएचजी) के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता था। इसके अलावा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना भी बीएमबी का उद्देश्य था। बीएमबी का एक अनूठा आदर्श वाक्य है 'महिलाओं को सशक्त बनाना, भारत का सशक्तिकरण (इम्पावरिंग वुमेन, इमपावरिंग इंडिया)', जो स्पष्ट रूप से इस संगठन के पीछे की मंशा को जाहिर करता है। हलाकि 31 मार्च 2017 को भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है, लेकिन उस मुकाबले में नहीं हो रहा है जैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बराबर भागीदारी और महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। बैंक ऑफ इंडिया स्टार महिला गोल्ड लोन स्कीम प्रतिष्ठित ज्वैलर्स / या बैंक ऑफ इंडिया से सोने के सिक्के, हॉलमार्क ज्वैलरी, सोने के गहने खरीदने के लिए कामकाजी / गैर– कामकाजी महिलाओं को बैंक ऋण सुविधा प्रदान करता है।

अतः मेरे इस शोध पत्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि सभी प्रमुख बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिला सशक्तिकरण के लिए लक्षित नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया है। इसमें कई महत्वपूर्ण महिला केंद्रित बैंक शामिल हैं और केवल महिलाओं को ही वित्तीय योजनाएं प्रदान करते हैं। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 डॉ मधु ग्रामीण विकास : आत्मनिर्भर भारत का आधार 2023 पृ0 77

2 एस आर महेश्वरी Rurual Development in india A public policy Approach P 91

3 Dainiknavajyoti Dailyhunt भारत में पंचायती राज व्यवस्था का परिचय पृ0 34

4 सुमन कुमारी आलम भारत की पंचायतीराज व्यवस्था का एक परिचय पृ0 97